

## IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट- भाग 2

### प्रलिस के लयः

जलवायु परवऱतन (IPCC), जलवायु परवऱतन, गैर-संचारी रोग, क्योटो प्रोटोकॉल, गरीनहाउस गैसों पर अंतर-सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट

### मेन्स के लयः

जलवायु परवऱतन (IPCC) पर अंतर-सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट, जलवायु परवऱतन, अनुकूलन उपाय, जलवायु परवऱतन का प्रभाव

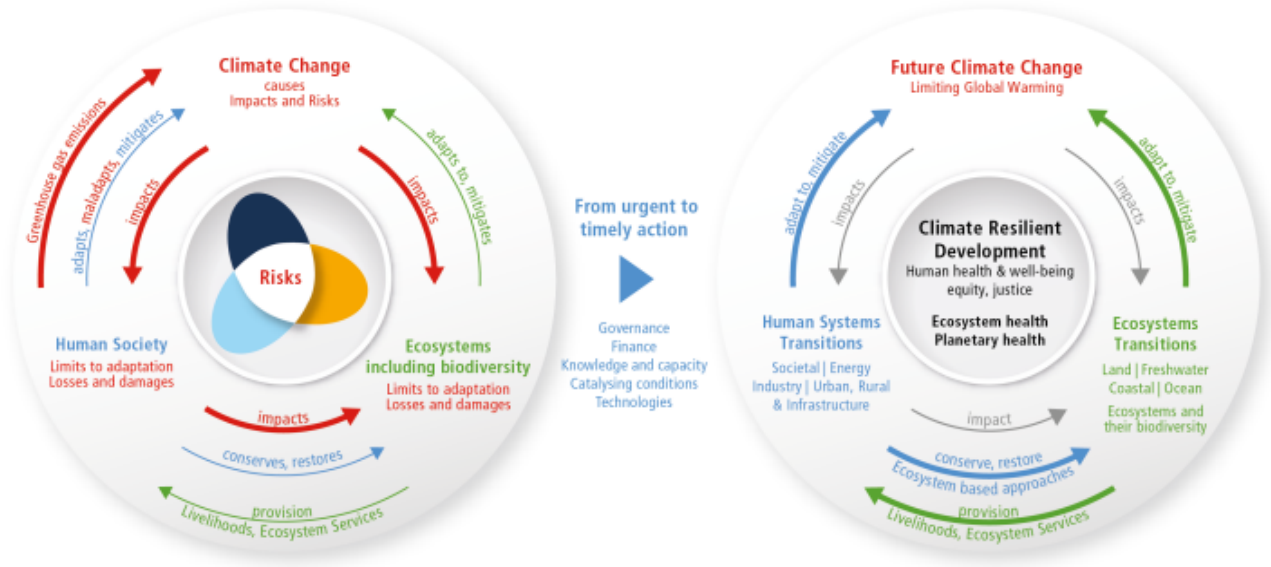
### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [जलवायु परवऱतन पर अंतर-सरकारी पैनल \(IPCC\)](#) ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी कयऱ। रिपोर्ट का यह दूसरा भाग जलवायु परवऱतन के प्रभावों, ज़ोखमिों और कमज़ोरयिों एवं अनुकूलन वकिल्पो से संबधति है।

- इस रिपोर्ट का पहला भाग वर्ष 2021 में जलवायु परवऱतन के भौतिक वजिज्ञान से संबधति थऱ। इसमें यह बताया गया थऱ कवऱर्ष [2040 से पहले ही वैश्वकि तापमान में 1.5 डगऱरी सेल्सयऱस की वृद्धि](#) की संभावना है।
- रिपोर्ट का तीसरा और अंतमि भाग, जो उत्सर्जन को कम करने की संभावनाओं पर ज़ोर देगा, अप्रैल 2022 में आने की उम्मीद है।

### रिपोर्ट के प्रमुख बढुः

- **ज़ोखमि में जनसंख्या:** वैश्वकि आबादी के 45% से अधकि 3.5 बलियन से अधकि लोग जलवायु परवऱतन के लयऱ अत्यधकि संवेदनशील कषेत्रों में रह रहे है।
- **भारतीय परदृश्य:** रिपोर्ट में भारत को एक संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप पहचाना गया है, जसिमें कई कषेत्रों एवं महत्त्वपूर्ण शहरों में बाढसमुद्र के सत्र में वृद्धि तथा हीट वेव्स जैसी जलवायु आपदाओं जैसे ज़ोखमिों का सामना करना पड रहा है।
  - उदाहरण के लयऱ मुंबई में समुद्र के सत्र में वृद्धिके साथ बाढ का उच्च ज़ोखमि है, जबकि अहमदाबाद में हीट वेव्स का गंभीर खतरा है।
- **जटलि, मशरति और व्यापक ज़ोखमि:** नवीनतम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जलवायु परवऱतन के साथ-साथ कई अन्य आपदाएँ अगले दो दशकों में वशिव के वभिन्न हसिंसों में उभरने की संभावना है।
  - कई जलवायु खतरे एक साथ घटति होंगे तथा जलवायु एवं गैर-जलवायु ज़ोखमि परस्पर क्रयऱ करेंगे, जसिके परिणामस्वरूप समग्र ज़ोखमि व खतरा सभी कषेत्रों में बढेंगे।
- **दीर्घकालकि ज़ोखमिों के नकिट:** भले ही पूर्व-औद्योगकि समय से वैश्वकि तापमान में वृद्धिको 1.5 डगऱरी सेल्सयऱस से कम रखने हेतु पर्याप्त प्रयास कयऱ गए हों।
  - यहाँ तक कि अस्थायी रूप से वैश्वकि तापमान में वृद्धि से कुछ अतरिकित्त गंभीर प्रभाव का सामना करना पड सकता है, जनिमें से कुछ अपरवऱतनीय भी हो सकते है।
  - जलवायु परवऱतन में वृद्धि तथा इससे जुडे ज़ोखमि नकिट अवधिके शमन तथा अनुकूलन कार्यों पर काफी हद तक नरिभर करते हैं।
  - अनुमानति प्रतकिल प्रभाव और संबधति नुकसान वैश्वकि तापमान में वृद्धिके साथ बढते हैं।
- **युगमति प्रणाली:** युगमति प्रणाली जलवायु, पारसिथतिकि तंत्र (उनकी जैव वविधिता सहति) और मानव समाज के बीच बातचीत पर एक मज़बूत ध्यान है।



- **क्षेत्रीय भिन्नता:** पारस्थितिक तंत्र और लोगों की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता क्षेत्रों के बीच और भीतर काफी भिन्न होती है।
  - ये सामाजिक-आर्थिक विकास, अस्थिर महासागर और भूमि उपयोग, असमानता, हाशिए पर, ऐतिहासिक तथा असमानता के चल रहे पैटर्न जैसे उपनिवेशवाद एवं शासन के प्रतिच्छेदन के पैटर्न से प्रेरित हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभाव:** यह पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से एशिया के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मलेरिया या डेंगू जैसे वेक्टर जनित और जल जनित रोग बढ़ रहे हैं।
  - इसमें यह भी कहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ संचार, श्वसन, मधुमेह और संक्रामक रोगों के साथ-साथ शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होने की संभावना है।
  - हीटवेब्स, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और यहाँ तक कि वायु प्रदूषण भी कुपोषण, एलर्जी संबंधी बीमारियों और यहाँ तक कि मानसिक विकारों को भी उत्पन्न कर रहा था।
- **वर्तमान अनुकूलन और इसके लाभ:** अनुकूलन योजना और कार्यान्वयन में प्रगत सभी क्षेत्रों में देखी गई है, जिसके कई लाभ हुए हैं।
  - कई पहलें तत्काल और निकटवर्ती जलवायु जोखिम में कमी को प्राथमिकता देती हैं जो परिवर्तनकारी अनुकूलन के अवसर को कम करती हैं।

## अनुकूलन जोखिम और रणनीतियाँ

System transitions	Representative key risks	Climate responses <sup>1</sup> and adaptation options
Land and ocean ecosystems	Coastal socio-ecological systems	Coastal defence and hardening Integrated coastal zone management
	Terrestrial and ocean ecosystem services	Forest-based adaptation <sup>2</sup> Sustainable aquaculture and fisheries Agroforestry Biodiversity management and ecosystem connectivity
	Water security	Water use efficiency and water resource management
	Food security	Improved cropland management Efficient livestock systems
Urban and infrastructure systems	Critical infrastructure, networks and services	Green infrastructure and ecosystem services Sustainable land use and urban planning Sustainable urban water management
	Water security	Improve water use efficiency
Energy systems	Critical infrastructure, networks and services	Resilient power systems Energy reliability
	Human health	Health and health systems adaptation
Cross-sectoral	Living standards and equity	Livelihood diversification
	Peace and human mobility	Planned relocation and resettlement Human migration <sup>3</sup>
	Other cross-cutting risks	Disaster risk management Climate services, including Early Warning Systems Social safety nets Risk spreading and sharing



- अनुकूलन में अंतराल: रिपोर्ट में कथि जा रहे अनुकूलन कार्यों और आवश्यक प्रयासों में बड़े अंतराल पर भी प्रकाश डाला गया है। यह बताती है कथि अंतराल "धन की कमी, राजनीतिक प्रतबिद्धता, वशिवसनीय जानकारी और तात्कालिकता की भावना" का परिणाम है।
  - नुकसान को कम करने के लिये अनुकूलन आवश्यक है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वाकांक्षी कटौती की जानी चहयि क्योकि बढती गर्मी के साथ कई अनुकूलन विकल्पों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- समग्र परिवर्तनों की आवश्यकता: अब यह स्पष्ट है कि भामूली, सीमांत, प्रतिक्रियाशील या वृद्धशील परिवर्तन पर्याप्त नहीं होंगे।
  - तकनीकी और आर्थिक परिवर्तनों के अलावा अनुकूलन की सीमाओं को पार करने, लचीला बनाने, जलवायु जोखिम को सहनीय स्तरों तक कम करने, समावेशी, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण विकास की गारंटी देने और किसी को पीछे छोड़े बना सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समाज के अधिकांश पहलुओं में बदलाव की आवश्यकता है।

## जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल

- यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है।
- IPCC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और वशिव मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation-WMO) द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके नहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा शमन के विकल्प भी उपलब्ध कराता है।
- IPCC आकलन जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने हेतु सभी स्तरों पर सरकारों के लिये एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं और वे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) में इस पर परचिर्चा करते हैं।

## IPCC आकलन रिपोर्ट

- आकलन रिपोर्ट, जो कि पहली बार रिपोर्ट वर्ष 1990 में सामने आई थी, पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक मूल्यांकन है।
  - प्रत्येक सात वर्षों में IPCC मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है।
- बदलती जलवायु को लेकर एक सामान्य समझ विकसित करने हेतु सैकड़ों वैश्वीय प्रसंगिक, प्रकाशित वैज्ञानिक जानकारी के हर उपलब्ध स्रोत का अध्ययन करते हैं।
- अन्य चार मूल्यांकन रिपोर्टें वर्ष 1995, वर्ष 2001, वर्ष 2007 और वर्ष 2015 में प्रकाशित हुईं।

- ये रपिर्त जलवायु परविरतन के प्रत वैश्वकि प्रतकिरयि का आधर हैं ।
- प्रतयेक मूल्यांकन रपिर्त में पछिली रपिर्त के काम पर अधकि सबूत, सूचना और डेटा एकत्रति कयि जतत है ।
  - तकि जलवायु परविरतन और उसके प्रभावों के वषिय में अधकि स्पष्टता, नश्चितिता और नए साक्ष्य मौजूद हों ।
- इन्ही वरतारों ने पेरसि समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल को जन्म दयि थ।
  - पाँचवी आकलन रपिर्त के आधर पर पेरसि समझौते पर वरतत हुई थी ।
- आकलन रपिर्त- वैज्ञानिकों के तीन कर्य समूहों द्वारा
  - **कर्यकारी समूह- I** : जलवायु परविरतन के वैज्ञानिकि आधर से संबंधति है ।
  - **कर्यकारी समूह- II** : संभावति प्रभावों, कमजोरयिों और अनुकूलन मुददों को देखतत है ।
  - **कर्यकारी समूह-III** : जलवायु परविरतन से नपिटने के लयि की ज सकने वली कररवाइयों से संबंधति है ।

## स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ipcc-part-two-of-sixth-assessment-report>

